RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 24 NOVEMBER TO 30 NOVEMBER 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 12 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

कृषि कानूनों की वापसी का पहला कदम, कैबिनेट से मंजूरी Page 3

अफगानिस्तान से खरबों डॉलर का दुर्लभ 'खजाना' निकालने पहुंचा चीन Page 4

इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के तहत स्कोडा के दूसरे मॉडल का बाज़ार में आगमन Page 5

editoria!

कर्ज का फर्जीवाड़ा

वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए या किसी मजबूरी में कर्ज लेना स्वाभाविक है. बैंकों और अन्य संस्थाओं से निर्धारित ब्याज दर पर धन मुहैया कराया जाता है, पर नियमों की वजह से बहुत से लोग इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाते हैं. उन्हें सूदखोरों से भारी ब्याज पर कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है. डिजिटल तकनीक की आमद ने एक ओर जहां बैंकिंग व्यवस्था को सरल और सुलभ बनाया है, तो दूसरी ओर इसके जरिये फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी भी खूब हो रही है. रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक समिति ने पाया है कि ऐंड्रॉयड फोन पर उपलब्ध पर्सनल लोन के 11 सौ एप में आधे से अधिक अवैध हैं, जो बिना किसी पंजीकरण या अनुमति के चल रहे हैं. इस गैरकानूनी कारोबार के फैलाव का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि अवैध एप 80 एप स्टोर पर उपलब्ध हैं.

ये एप सस्ते दरों पर तुरंत कर्ज देने का वादा करते हैं. किसी तरह कर्ज हासिल करने की बेताबी के चक्कर में लोग इन्हें अपने खाते, आधार कार्ड, आय से जुड़े दस्तावेज आदि दे देते हैं, जिनके दुरुपयोग की आशंका रहती है. एक बार कर्ज की राशि देने के बाद मनमाने ढंग से ब्याज वसूली का दौर शुरू होता है और लेनदार से अभद्र व्यवहार भी किया जाता है. ऐसे मामले भी सामने आये हैं, जहां खाते से पैसे उड़ा लिये गये हैं. कोरोना काल में नौकरियां छूटने और कारोबार बंद होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने ऐसे एप के जरिये कर्ज उठाया है. बड़ी संख्या में शिकायतें आने के बाद रिजर्व बैंक ने इस साल जनवरी में समिति का गठन किया था. अब इसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हो रही है. ऐंड्रॉयड सेवाएं देनेवाली कंपनी गूगल से अवैध एप की जानकारी मांगी गयी है. ऐसे संकेत मिले हैं कि अवैध लेनदेन के कारोबार में विदेशों में स्थित कंपनियां शामिल हैं. ऐसे में यह वित्तीय नियमन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न भी है. इसकी गंभीरता को देखते हुए रिजर्व बैंक ने सरकार से डिजिटल माध्यम से कर्ज लेने और देने के बारे में अलग से कानून बनाने के संबंध में विचार करने का आग्रह किया है. ऐसे कारोबार में लगे भारतीय उद्यमों को भी विशेष नियम बनाने को कहा गया है. इस मसले पर ठोस पहल के लिए सभी संबद्ध पक्षों से इस साल के अंत तक अपनी राय देने का आग्रह भी किया गया है. यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और निजी बैंकों द्वारा दिये गये डिजिटल ऋण की मात्रा में कुछ समय से तेज बढ़ोतरी हुई है.

अर्थव्यवस्था में सुधार और तकनीकी बेहतरी के साथ इसमें लगातार बढ़त की उम्मीद भी है. ऐसे में अवैध कारोबारियों की सेंधमारी से कारोबार और लोगों को बचाना जरूरी है. लोगों को भी पंजीकृत संस्थाओं से ही कर्ज लेना चाहिए, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं.

सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल

स्ट्रैटेजिक रिजर्व से 50 लाख बैरल कच्चा तेल निकालेगा भारत

नई दिल्ली । आईपीटी नेटवर्क

भारत कच्चे तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए जारी अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का हिस्सा बनते हुए अपने रणनीतिक तेल भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल जारी करेगा। इससे देश में पेट्रोल डीजल की कीमत और कम होगी। केंद्र सरकार ने बयान जारी कर रणनीतिक तेल भंडार से 50 लाख बैरल तेल की निकासी करने के फैसले की जानकारी दी। यह पहला मौका है जब भारत अपने रणनीतिक भंडार से कच्चे तेल की निकासी करेगा। इससे कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों को नीचे लाने में मदद मिलेगी। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल उपभोक्ता देश है।

भारत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल जारी करने पर सहमत हुआ है। यह कदम अमेरिका, चीन, जापान एवं दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख तेल उपभोक्ता देशों के साथ तालमेल बनाकर उठाया गया है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते-दस दिन में तेल निकासी की प्रक्रिय शुरू हो जाएगी। भारत कई बार इस बात पर चिंता जताई है कि तेल उत्पादक देश तेल की आपूर्ति को कृत्रिम ढंग से मांग से कम रखते हैं। इससे तेल की कीमतें बढ़ती हैं और नकारात्मक नतीजे सामने आते हैं। भारत ने अपने पश्चिमी एवं पूर्वी दोनों तटों पर रणनीतिक तेल भंडार बनाए हुए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और कर्नाटक के मंगलूरु एवं पदुर में ये भूमिगत तेल भंडार बनाए गए हैं। इनकी सामूहिक भंडारण क्षमता करीब 3.8 करोड़ बैरल की है। भारत ने यह कदम तेल उत्पादक देशों की तरफ से कीमतों में कमी लाने के लिए उत्पादन बढ़ाने से इनकार करने के बाद उठाया है। इसके लिए अमेरिका ने भारत के अलावा चीन एवं जापान से भी मिलकर प्रयास करने का अनुरोध किया था।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 78 डॉलर प्रति बैरल पर हैं। पिछले महीने यह 86 डॉलर प्रति बैरल से भी ज्यादा हो गया था लेकिन यूरोप के कुछ देशों में फिर से लॉकडाउन लगने और प्रमुख उपभोक्ता देशों के मिलकर सुरक्षित तेल जारी करने की धमकियों से इसमें थोड़ी गिरावट आई है।

अक्टूबर में कच्चा तेल उत्पादन घटा, प्राकृतिक गैस उत्पादन 25% बढ़ा

नयी दिल्ली । एजेंसी

भारत का कच्चे तेल का उत्पादन अक्टूबर में 2.15 प्रतिशत घट गया, जबकि प्राकृतिक गैस का उत्पादन 25 प्रतिशत बढ़ गया। सरकार की तरफ से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर, 2021 में सरकारी स्वामित्व वाली पेट्रोलियम कंपनियों का उत्पादन कम होने से कच्चे तेल का उत्पादन घटकर 25.1 लाख टन रहा।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर महीने में ओएनजीसी का कच्चा तेल उत्पादन चार फीसदी कम रहा जबकि ऑयल इंडिया (ओआईएल) का उत्पादन 1.46 प्रतिशत नीचे आया। तेल के मामले में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके बावजूद भारत अपनी 85 प्रतिशत तेल जरूरत आयात से ही पूरी करता है। दूसरी तरफ प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा साबित हुआ। रिलायंस-बीपी के केजी-डी6 क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ने से इस माह प्राकृतिक गैस का उत्पादन 25 प्रतिशत बढ़ गया।

बीते महीने भारत में 3.01 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन हुआ जो 24.7 प्रतिशत अधिक है। इसमें निजी कंपनियों के शानदार प्रदर्शन का योगदान रहा क्योंकि सरकारी कंपनी ओएनजीसी का उत्पादन 4.4 प्रतिशत गिरा है। अक्टूबर में तेल शोधन गतिविधियों में भी बढ़त दर्ज की गई। मांग बढ़ने की वजह से इस महीने में तेलशोधन इकाइयों ने अक्टूबर, 2020 की तुलना में 14 प्रतिशत ज्यादा कच्चे तेल का शोधन किया।

क्रिप्टोकरेंसी पर मोदी सरकार की सख्ती, एलन मस्क की बढ़ेगी टेंशन!

नई दिल्ली । एजेंसी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसने के मूड में नजर आ रही है। दरअसल, सरकार आगामी संसद के शीतकालीन सत्र क्रिप्टोकरंसी से जुड़े विधेयक लाने की तैयारी में है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में सभी तरह के निजी क्रिप्टोकरंसी को प्रतिबंधित किया जाएगा। ये खबर उन निवेशकों के लिए बड़ा झटका है जो क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं या इसकी योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के लिए भी ये खबर टेंशन बढ़ाने वाली है।

दरअसल, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला भारतीय बाजार में एंट्री करने वाली है। टेस्ला के मुखिया एलन मस्क क्रिप्टोकरेंसी के दीवाने हैं। वह समय-समय पर बिटक्वाइन समेत अन्य कई क्रिप्टोकरेंसी को प्रमोट भी कर चुके हैं। यही नहीं, बीते दिनों टेस्ला ने अमेरिका में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के लिए बिटक्वाइन को भुगतान के रूप में स्वीकार करने की भी घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने दुनियाभर में इसकी स्वीकार्यता के संकेत दिए थे। ऐसे में ये माना जा रहा था कि भविष्य में टेस्ला भारत में भी क्रिप्टोकरेंसी से पेमेंट के तरीके पर काम कर सकती है।

(शेष पेज 2 पर)

डल्स्को ने यूएई में अनोखा ऑयल री-रिफाइनरी प्लांट लॉन्च किया

दुबई। एजेंसी

डल्स्को ग्रुप के एनवायर्नमेंटल सॉल्यूशंस वर्टिकल ने एक उन्नत ऑयल री-रिफाइनरी प्लांट लॉन्च किया है, जो इस क्षेत्र में अपनी तरह का पहला प्लांट है। जेबेल अली में स्थित यह सुविधा 14,000 वर्गमीटर में फैली हुई है। किसी भी उद्योग के भीतर प्रगति एक दुर्भाग्यपूर्ण उप-उत्पाद "WASTE" की कीमत पर आती है। देश के विकास प्रयासों के एक अभिन्न अंग के रूप में यूएई के मूल्य स्थिरता और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी प्रगतिशील रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अत्यंत महत्व के साथ माना जाता है।

प्रौद्योगिकी और नवाचार में भारी निवेश करते हुए डल्स्को स्थिरता के लिए यूएई के एजेंडे और एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के देश के मिशन का सहयोग करना चाहता है। डल्स्को के सीईओ डेविड स्टॉकटन ने कहा, 'हमारी प्राथमिकता भविष्य के लिए स्थायी बुनियादी ढांचे को लागू करने में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाना है। हम यह सुनिश्चित करके ऐसा करते हैं कि हमारे मूल्यों को सर्कुलर अर्थव्यवस्था में सर्वोत्तम प्रथाओं और रीसाइक्लिंग परियोजनाओं में निवेश, विशेषज्ञता और शिक्षा के माध्यम से लागू किया जाता है।'

विशेषज्ञ जनशक्ति और अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए डल्स्को ने देश के बंदरगाहों और तेल व गैस क्षेत्रों जैसे जटिल उद्योगों की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और सेवाओं का विकास किया है। कंपनी का हालिया निवेश एक अत्याधुनिक तेल रिफाइनरी सुविधा है, जो प्रति माह लगभग 1,400 टन तेल अपशिष्ट व समुद्री, तेल, गैस और औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न 600 स्लज को संसाधित करने में सक्षम है। एक प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में दुबई में जेबेल अली और रशीद के बंदरगाह में दैनिक समुद्री यातायात अधिक है, जिसके लिए आईएमओ-मारपोल मानकों के अनुरूप समुद्री कचरे के सुरक्षित निपटान की सुविधा की आवश्यकता होती है।

डल्स्को दुबई में एकमात्र कचरा प्रबंधन कंपनी है, जिसे मार्पोल अनुबंध 1, 2, 3, 4 और 5 के अनुसार सभी प्रकार के समुद्री कचरे को संभालने की मंजूरी दी गई है। 'डल्स्को की री-रिफाइनरी सुविधा से दुबई के समुद्री उद्योग के विभिन्न तैलीय अपशिष्टों का पूरी तरह से एकीकृत समाधान प्रदान करने के लक्ष्य में वृद्धि हुई है ताकि पर्यावरण और हमारे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा में मदद मिल सके। अपशिष्ट, तेल और तैलीय कीचड़ में खतरनाक घटक होते हैं। यदि बिना उपचार के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो जहरीले घटक हमारे पर्यावरण में छोड़े जाते हैं, जो हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा और हमारे द्वारा पीने वाले जल को प्रदूषित करते हैं।' अपशिष्ट तेल या तैलीय कीचड़ अपशिष्ट आपूर्ति श्रृंखला में अनियंत्रित रहने के बजाय इसे उच्चतम मानकों के अनुसार एकत्र, उपचारित और पुनः उपयोग किया जाएगा। डल्स्को का पूरी तरह से एकीकृत और प्रोग्राम करने योग्य तर्क नियंत्रित (पीएलसी) संयंत्र एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के साथ प्राप्त तैलीय कचरे को संसाधित करता है, जिससे हल्के और भारी ईंधन दोनों का उत्पादन होता है। भारी ईंधन का उपयोग बर्नर और भट्टियों के लिए किया जाता है, जबकि घर में उत्पन्न होने वाले हल्के ईंधन का उपयोग प्रक्रिया संचालन के लिए किया जाता है। संयंत्र से प्राप्त जल को अतिरिक्त रूप से उपचारित किया जाता है और डल्स्को की जल उपचार सुविधा में सिंचाई गुणवत्ता वाले जल में परिवर्तित किया जाता है और इसके बॉयलर में पुनः उपयोग किया जा सकता है या अंतिम उपयोगकर्ताओं को उनकी सिंचाई आवश्यकताओं के लिए प्रदान किया जा सकता है।

रुपया दो पैसे की तेजी के साथ 74.40 प्रति डॉलर पर

मुंबई । एजेंसी

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक का ब्योरा जारी होने से पहले रुपये की आरंभिक हानि लुप्त हो गयी और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बुधवार को भारतीय मुद्रा दो पैसे की तेजी के साथ 74.40 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 74.53 के स्तर पर कमजोर रुख लिए खुला और कारोबार के दौरान यह दिन के उच्चतम स्तर 74.31 रुपये और निम्नतम स्तर 74.54 रुपये को छूने के बाद अंत में डॉलर के मुकाबले दो पैसे की तेजी के साथ 74.40 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। मंगलवार को यह 74.42 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स कारोबार के अंत में 323.34 अंक की गिरावट के साथ 58,340.99 अंक पर बंद हुआ। छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.22 प्रतिशत बढ़कर 96.70 हो गया। इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.24 प्रतिशत घटकर 82.11 डॉलर प्रति बैरल रह गया।

सेंसेक्स 323 अंक टूटा, निफ्टी 17415 पर बंद; इन्फोसिस, रिलायंस में नुकसान

मुंबई । एजेंसी

शेयर बाजार में बुधवार को कारोबार के आखिरी घंटे में की गई बिकवाली से बीएसई सेंसेक्स 323 अंक से अधिक लुढ़क गया। मुख्य रूप से इन्फोसिस, रिलायंस और एचडीएफसी में नुकसान से बाजार में गिरावट आई। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स कारोबार के दौरान ज्यादातर समय बढ़त में था। पर अंत में यह बिकवाली दबाव से 323.34 अंक यानी 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58,340.99 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 88.30 अंक यानी 0.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,415.05 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में मारुति, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, आईटीसी, रिलायंस, एलएंडटी, अल्ट्राटेक सीमेंट और एचडीएफसी सर्वाधिक 2.62 प्रतिशत तक नुकसान में रहे। दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस और पावरग्रिड शामिल हैं। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 नुकसान में रहे।

हीरो इलेक्ट्रिक की त्योहारी सीजन की बिक्री दोगुना होकर 24,000 इकाई पर

नयी दिल्ली। एजेंसी

हीरो इलेक्ट्रिक की त्योहारी सीजन (एक अक्टूबर से 15 नवंबर) की खुदरा बिक्री पिछले साल की समान अवधि की तुलना में दोगुना से अधिक होकर 24,000 इकाई रही है। कंपनी ने एक बयान में यह जानकारी दी। पिछले साल समान अवधि में कंपनी ने 11,339 वाहन बेचे थे।

कंपनी ने कहा कि फेम दो (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वेहिकल्स इन इंडिया) नीति में हालिया संशोधन से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ी है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया पर अग्रिम प्रोत्साहन दिया जाता है। हीरो इलेक्ट्रिक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सोहिंदर गिल ने कहा, ''इस सीजन में हमें अपने शोरूम पर दो स्पष्ट संकेत देखने को मिले। बड़ी संख्या में ग्राहकों ने पेट्रोल बाइक की तुलना में हीरो ई-बाइक को प्राथमिकता दी। वहीं बड़ी संख्या में ग्राहकों ने पर्यावरण और टिकाऊ क्षमता की वजह से ऐसी बाइक खरीदीं।''

ओपेक ने तोड़ा वादाः

अक्तूबर में और घटाया तेल उत्पादन, 116 फीसदी की बड़ी कटौती

नई दिल्ली । एजेंसी

तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक व अन्य सहयोगी देशों ने अक्तूबर में तेल उत्पादन और घटा दिया। ओपेक-प्लस ने क्रूड की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए उत्पादन बढ़ाने का भरोसा दिया था। ओपेक-प्लस ने सितंबर में जहां अपनी कुल उत्पादन क्षमता में 115 फीसदी कटौती की थी, वहीं अक्तूबर में इसे बढ़ाकर 116 फीसदी कर दी। पिछले दिनों ओपेक-प्लस देशों की बैठक में सऊदी अरब सहित अन्य उत्पादकों ने कीमतें थामने के लिए आपूर्ति बढ़ाने का भरोसा दिया था, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है।इस बीच ओपेक ने अपने संगठन में शामिल होने के नियमों को और भी सख्त बना दिया है, जबकि गैर ओपेक देश के रूप में उत्पादन करने वाले देशों पर नियमों का बोझ कम हुआ है। यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट की आशंका के चलते शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड की कीमतों में कमी आई। ब्रेंट क्रूड 2.78 डॉलर गिरकर 78.46 डॉलर प्रति बैरल के भाव आ गया। यह पिछले डेढ़ महीने का सबसे निचला स्तर है।

भारत बोला...50 लाख बैरल अतिरिक्त तेल को बाजार में लाए ओपेक

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि ओपेक व सहयोगी देशों को 50 लाख बैरेल की अतिरिक्त क्षमता वाले तेल को बाजार में लाना चाहिए, ताकि कीमतों पर लगाम कसी जा सके। 2021 में क्रूड की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 60 फीसदी बढ़ चुकी हैं। पुरी ने कहा, हम तेल उत्पादक देशों के पास जाकर उन्हें कीमतें घटाने के लिए नहीं कह सकते। यह उनकी जिम्मेदारी है कि अपने आयातक देशों को किफायती कीमत पर ईंधन उपलब्ध कराया जाए। पुरी ने सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और रूस के पेट्रोलियम मंत्रियों के साथ बैठक भी की।

हाजिर मांग के कारण कच्चा तेल वायदा कीमतों में तेजी

नई दिल्ली । एजेंसी

मजबूत हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों का आकार बढ़ाया जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को कच्चे तेल की कीमत छह रुपये की तेजी के साथ 5,889 रुपये प्रति बैरल हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कच्चातेल के दिसंबर माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत छह रुपये अथवा 0.1 प्रतिशत की तेजी के साथ 5,889 रुपये प्रति बैरल हो गई जिसमें 4,261 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने से वायदा कारोबार में कच्चा तेल कीमतों में तेजी आई। हालांकि, वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में वेस्ट टैक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का दाम 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78.78 डालर प्रति बैरल रह गया। इस बीच, वैश्विक मानक माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड का दाम 0.35 प्रतिशत घटकर 82.60 डालर प्रति बैरल रह गया।

क्रिप्टोकरेंसी पर मोदी सरकार की सख्ती, एलन मस्क की बढ़ेगी टेंशन!

पेज 1 का शेष

हालांकि, कुछ दिनों बाद टेस्ला ने अमेरिका में क्रिप्टोकरेंसी से पेमेंट पर रोक लगा दी। अब फिर कंपनी ने इसे शुरू करने के संकेत दिए हैं। बहरहाल, भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर बैन की स्थिति में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की प्लानिंग को झटका लग सकता है। आपको बता दें कि टेस्ला की कार जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। कार लॉन्चिंग से पहले टेस्ला, भारत सरकार से आयात शुल्क को कम करने की भी मांग कर रही है। बहरहाल, खबर ये भी है कि केंद्रीय रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है। अब देखना अहम होगा कि इस डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग के क्या तरीके होंगे और इसकी कितनी स्वीकार्यता होगी। ये भी देखना होगा कि क्या टेस्ला जैसी विदेशी कंपनियां भारतीय डिजिटल करेंसी को स्वीकार करेंगी या नहीं।

मध्य भारत में तेज विकास की राह पर रोका पैरीवेयर

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत के प्रमुख बाथरूम प्रोडक्ट्स मैन्यूफैक्चरर्स और प्रीमियम बाथरूम सॉल्यूशंस की अग्रणी कंपनी, रोका बाथरूम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेडने मध्य भारत में अपने बिजनेस ऑपरेशंस बढ़ाने की योजना की घोषणा की। कोविड के बाद सफल विकास दर्ज करने वाली गिनी-चुनी कंपनियों में से एक, रोका पैरीवेयर अपनी पहुंच का विस्तार करने और मध्य प्रदेश के बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने के लिए तैयार है। कंपनी की अगले वर्ष की योजना के बारे में बताते हुए, रोका इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री के. ई. रंगनाथन ने कहा कि 'एक कंपनी के रूप में, हमने कोविड के बाद के बाजार में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमारे सुपर-प्रीमियम ब्रांड, रोका ने लगातार प्रगति करते हुए मध्य प्रदेश में 30% की वृद्धि दर्ज की है। बाथरूम प्रोडक्ट्स के बाजार में अग्रणी पैरीवेयर ने पिछले साल महामारी के असर के बावजूद 70% वृद्धि दर्ज की है। मध्य प्रदेश (देवास) का एक भारतीय ब्रांड जॉनसन पेडर लगातार प्रगति कर रहा है और इसने मध्य प्रदेश में 83 प्रतिशत की भारी वृद्धि हासिल की है। यह सब हमारे लिए ब्रांड की चौतरफा प्रगति का स्पष्ट संकेत है और हमारे पास आगे के विकास की बड़ी योजनाएं हैं।' मध्य प्रदेश के बाजार के लिए अपनी भावी योजनाओं के बारे में श्री के.ई. रंगनाथन ने बताया कि 'बाजार निवेश, नए प्रोडक्ट्स और लॉयल्टी प्रोग्राम पर ध्यान केंद्रित करके अपने विकास को जारी रखने की हमारी महत्वाकांक्षी योजना है।' उन्होंने आगे कहाकि 'देवास में हमारी सबसे बड़ी मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटी, 2022 के लिए टेक्नोलॉजी और वॉल्यूम रैंप-अप दोनों के लिए उच्च निवेश जारी रखेगी। हमें प्रसन्नता है कि हम मध्य प्रदेश में अपनी सीएसआर गतिविधियों के जरिये समाज में योगदान कर रहे हैं।'

चिटफंड की तरह फूट जाएगा क्रिप्टोकरेंसीज का बुलबुला-रघुराम राजन

नई दिल्ली। एजेंसी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने दावा किया है कि चिटफंड की तरह क्रिप्टोकरेंसीज का बुलबुला जल्दी ही फूट जाएगा और इनमें से अधिकांश का वजूद खत्म हो जाएगा। इस समय दुनिया में करीब 6,000 क्रिप्टोकरेंसीज हैं और राजन का कहना है कि इनमें से केवल 1 या दो ही बाकी रह जाएंगी। राजन ने एक इंटरव्यू में कहा कि अधिकांश क्रिप्टो का वजूद केवल इसलिए है कि कोई बेवकूफ उन्हें खरीदना चाहता है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसीज से देश में उसी तरह की समस्याएं होगी जैसी चिट फंड से हुई हैं। चिट फंड्स लोगों से पैसा लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। क्रिप्टो एसेट्स रखने वाले कई लोगों को आने वाले दिनों में परेशानी होगी। राजन ने कहा कि अधिकांश क्रिप्टो का कोई स्थायी मूल्य नहीं है लेकिन पेमेंट्स खासकर क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स के लिए कुछ क्रिप्टो का वजूद बना रह सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बनाए रखने के बारे में राजन ने कहा कि केंद्र सरकार को देश में इसे आगे बढ़ाने की इजाजत देनी चाहिए। सरकार ने कहना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की इजाजत दी जा सकती है।

सरकार बिटकॉइन जैसी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज पर बैन लगाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में एक बिल लाने की योजना बना रही है। इससे देश में अधिकारिक डिजिटल करेंसी का रास्ता भी साफ होगा। इसे आरबीआई जारी करेगा। आरबीआई ने प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज के खतरों से सरकार को आगाह किया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टोकरेंसीज को मेक्रोइकनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा बताया था।

कितने लोगों के पास है क्रिप्टोकरेंसी

भारत सहित पूरी दुनिया में क्रिप्टोकरेंसीज का क्रेज हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से अधिक लोगों के पास क्रिप्टोकरेंसी है। इसमें युवाओं के साथ सीनियर सिटीजंस भी शामिल हैं। भारत में क्रिप्टो ऑनर्स की संख्या अमेरिका से अधिक है। हालांकि होल्डिंग की वैल्यू के हिसाब से अमेरिका आगे है।

आर्थिक वृद्धि दर दूसरी तिमाही में 7.8 प्रतिशत, पूरे वित्त वर्ष में 9.4 प्रतिशत रहेगी : रिपोर्ट

मुंबई। एजेंसी

चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की आधिकारिक वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। एचडीएफसी बैंक के अर्थशास्त्रियों की तैयार की गई एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। बुधवार को जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021-22 में वास्तविक जीडीपी 9.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। हालांकि, वर्ष 2022-23 में इसके घटकर 7.5 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में महामारी की तगड़ी मार से जीडीपी में 7.3 प्रतिशत का संकुचन देखा गया था। वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 9.5 प्रतिशत वृद्धि का पूर्वानुमान जताया है जबकि वर्ष 2022-23 में इसके सुस्त पड़कर 7.8 प्रतिशत रहने की बात कही है। दरअसल वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं थी जिससे मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आधार कम है और इस साल उच्च वृद्धि दर रहने के पीछे इस निम्न आधार को ही बड़ा कारण बताया जा रहा है।चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में निम्न आधार की वजह से जीडीपी में करीब 20 प्रतिशत का उछाल आया था। जहां तक सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही के आधिकारिक आंकड़ों का सवाल है तो उसके 30 नवंबर को आने की उम्मीद है। एचडीएफसी बैंक की इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि दूसरी तिमाही में रहने वाली 7.8 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर के पीछे भी पिछले साल का निम्न आधार ही अहम कारण रहेगा। हालांकि इस तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी का भी असर नजर आएगा। जुलाई-सितंबर, 2020 में जीडीपी में 16.9 फीसदी का संकुचन आया था। यह रिपोर्ट कहती है, "दबी मांग के समर्थन और यात्रा संबंधी बंदिशें हटने से आर्थिक गतिविधियां अगस्त की शुरुआत में महामारी की दूसरी लहर से पहले की स्थिति में पहुंच गई और उसके बाद से मजबूत ही बनी हुई हैं।" इस रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर चार प्रतिशत रहेगी जबकि उद्योग क्षेत्र में यह 6.3 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र के लिए 8.6 प्रतिशत रहेगी। अगर सकल मूल्य-वर्द्धन के नजरिये से देखें तो दूसरी तिमाही में वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रह सकती है।

कपड़ों और जूतों पर 12 फीसदी जीएसटी को हटाने की मांग

नई दिल्ली। एजेंसी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा कपड़ों और जूतों पर लगाए गए 12 प्रतिशत जीएसटी का पूरे देश में विरोध हो रहा है। कपड़ों और जूतों पर जीएसटी को वापस लेने और ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर मुंबई समेत देशभर के व्यापारी बुधवार यानी आज विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। इस आंदोलन की घोषणा देश भर के व्यापारियों के नेतृत्व वाले संगठन, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा की गई है। CAIT के अधिकारियों के अनुसार रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं। रोटी पहले से ही महंगी है। घर बनाना भी मुश्किल हो गया है और

देशभर के व्यापारी देंगे धरना

अब सरकार ने कपड़ों और सभी संबंधित गतिविधियों पर 12 फीसदी जीएसटी लगाकर छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। कोरोना महामारी के बाद व्यापारी मुश्किल से ठेले पर उतर रहे हैं। छोटे कारोबारियों पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसलिए मुंबई समेत देशभर के कपड़ा व्यापारी संघों के साथ व्यापारी बुधवार को सरकार के फैसले के साथ-साथ अमेजन के खिलाफ भी आंदोलन करने को तैयार हैं।CAIT अधिकारियों के मुताबिक, नशीले पदार्थों ने आर्यन खान को शक के आधार पर गिरफ्तार किया और 23 दिनों तक जेल में रखा। उसके खिलाफ अमेज़न के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने वहां से मारिजुआना जब्त करने के बाद अमेज़ॅन के अधिकारियों पर भी आरोप लगाया है। इसलिए अमेज़न के संबंधित अधिकारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। Amazon के खिलाफ पुलवामा चैप्टर में भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। देश में कानून सभी लोगों के लिए समान होना चाहिए। अगर अब उनके खिलाफ देश का कोई व्यापारी होता तो बहुत पहले जेल में डाल दिया जाता। अपराध की गंभीरता के बावजूद, अमेज़न के किसी अधिकारी पर आरोप नहीं लगाया गया है।

कृषि कानूनों की वापसी का पहला कदम, कैबिनेट से मंजूरी, अब संसद में आएगा विधेयक

नई दिल्ली। एजेंसी

तीन नए कृषि कानूनों की वापसी की संवैधानिक प्रक्रिया का पहला कदम सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। बुधवार को मोदी सरकार की कैबिनेट ने इन कानूनों का वापसी वाले बिल को मंजूरी दे दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवार को ही इन कानूनों का वापसी का ऐलान किया था। अब इस पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद बिल को संसद के शीत सत्र में पेश किया जाएगा। संसद का सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है और पहले ही दिन यह बिल पेश होने वाला है। हालांकि अब भी संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े 40 संगठन दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि एमएसपी समेत 6 मांगों के पूरा होने पर ही घर वापसी करेंगे। इस बीच किसान संगठनों ने ऐलान

किया है कि 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टरों के साथ 1,000 किसान संसद की ओर कूच करेंगे। यही नहीं 26 नवंबर को किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन का फैसला लिया है। इसके अलावा 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से मीटिंग बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर फैसला लिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, 'जो सड़के सरकार द्वारा खोली गई हैं। उन सड़कों से ट्रैक्टर गुजरेंगे। हम पर पहले सड़कों को ब्लॉक करने का आरोप लगाया गया था। हमने सड़क को अवरुद्ध नहीं किया था। सड़कों को ब्लॉक करना करना हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है। हमारा आंदोलन सरकार से बात करना है। हम सीधे संसद जाएंगे।'

कई खाप पंचायतों की सलाह, अब खत्म कर देना चाहिए आंदोलन

हालांकि किसान आंदोलन के समर्थकों के बीच भी इसे जारी रखने या बंद करने को लेकर मतभेद पैदा हो गए हैं। चौबीस खाप और गठवाला खाप के नेताओं का कहना है कि अब इस आंदोलन को समाप्त करते हुए किसानों को घर वापसी कर लेनी चाहिए। वहीं कई खाप नेताओं ने आंदोलन को जारी रखने का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसपी को लेकर अभी संघर्ष चलते रहना चाहिए। बीते एक साल से किसान संगठन यूपी और हरियाणा से लगी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और इसके चलते कई रास्ते भी जाम हैं।

अफगानिस्तान से खरबों डॉलर का दुर्लभ 'खजाना' निकालने पहुंचा चीन

काबुल। एजेंसी

अफगानिस्तान की धरती में छिपे खरबों रुपये के दुर्लभ खजाने को निकालने की कोशिश चीन ने शुरू कर दी है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पृथ्वी के नीचे छिपे खरबों रुपये के दुर्लभ धातुओं को कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे उसका प्रोडक्शन किया जाए, इस बात की खोज करने के लिए चीनी प्रतिनिधिमंडलों की टीम अफगानिस्तान पहुंच चुका है और अपने काम कर लग चुका है। चीनी प्रतिनिधिमंडल की ये टीम अफगानिस्तान के गर्भ में छिपे बेहद दुर्लभ माने जाने वाली धातु लिथियम का खोज करेंगे।

अफगानिस्तान में प्रतिनिधिमंडल रिपोर्ट के मुताबिक, चीन का प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान में लिथियम निकालने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है और उन जगहों पर निरिक्षण की जा रही है, जहां पर लिथियम होने की संभावना है। आपको बता दें कि, लिथियम को बेहद दुर्लभ धातु कहा गया है और आने वाले वक्त में लिथियम जिसके पास होगा, वही दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की कई कंपनियों ने अफगानिस्तान से दुर्लभ धातुओं को निकालने में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि, अफगानिस्तान में अभी भी नीति, सुरक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।

अफगानिस्तान में पांच चीनी कंपनियां ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की पांच कंपनियों के अधिकारियों को अफगानिस्तान में दुर्लभ धातुओं के परीक्षण के लिए विशेष वीजा दिया गया है, जो इस वक्त अफगानिस्तान में उन जगहों पर मौजूद हैं, जहां पर लिथियम होने की संभावना जताई गई है। ये टीम शुरूआती जांच करेगी और फिर उसकी रिपोर्ट चीन की सरकार को सौंपेगी। इस टीम के डायरेक्टर यू मिंगहुई ने कहा कि, ''वे चाइनाटाउन पहुंचे हैं और अपनी योजना के अनुसार अफगानिस्तान में निरिक्षण कर रहे हैं''। उन्होंने कहा कि, ''चीन की कंपनियां अफगानिस्तान में व्यापार के अवसरों का पता लगाने में मदद कर रही हैं''। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ''इन कंपनी प्रतिनिधियों को चीनी निवेशकों को जारी किए गए विशेष वीजा का पहला बैच मिला है''।

तालिबान का व्यापारिक भागीदार बनेगा चीन

अगस्त में अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी के बाद से तालिबान को देश चलाने के लिए पैसों की जरूरत है और जापानी अखबार

निक्केई एशिया ने दावा किया है कि, चीन खुद को तालिबान का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक भागीदार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और तालिबान इस बात को जानता है कि, अफगानिस्तान में पैर जमाने के लिए चीन से बेहतर उसका विकल्प कोई और नहीं बन सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि, अफगानिस्तान में एक ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन डॉलर की दुर्लभ सामग्री मौजूद है। खासकर अफगानिस्तान में लिथियम का अपार भंडार छिपा हुआ है।

अमेरिका ने खोजा था खजाना

2004 में अमेरिका द्वारा तालिबान की सत्ता को बर्खास्त कर दिया गया। जिसके बाद अमेरिकन जियोलॉजिकल सोसायटी के सर्वेक्षण ने अफगानिस्तान के अंदर एक सर्वेक्षण शुरू किया था। 2006 में अमेरिकी शोधकर्ताओं ने चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण और हाइपरस्पेक्ट्रल सर्वेक्षणों के लिए हवाई मिशन भी किए थे। जिसमें पता चला था कि अफगानिस्तान में अकूत मात्रा में लोहा, तांबा, कोबाल्ट, सोना के अलावा औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण लिथियम और नाइओबियम के विशालकाय खनिज मौजूद है। ये ऐसे खनिज हैं, जो रातों रात किसी भी देश की तकदीर को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। वहीं, नाटो के 16वें सुप्रीम एलाइड कमांडर जेम्स स्टावरिडिस ने कहा है कि, ''चीन माइक्रोचिप्स से लेकर इलेक्ट्रिक कार बैटरी तक हर चीज के लिए रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला पर जितना हो सके उतना नियंत्रण मजबूत करना चाहता है, इसीलिए वो काबुल में प्रधानता चाहते हैं।'

पाकिस्तान भी मारेगा एंट्री?

विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान खनिज संपदा के दोहन और तालिबान शासन के साथ भारत की भूमिका को रोकने में चीन के साथ साझेदारी करने की कोशिश करेगा। 19वीं शताब्दी में अफगानिस्तान में ज्यादातर वक्त तक रूस और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में संघर्ष किया है।

वहीं, भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने अफगानिस्तान की रणनीतिक स्थिति और दक्षिण एशिया को प्रभावित करने की इसकी क्षमता को मान्यता दी। वहीं, पाकिस्तान की भूमिका पर कुछ विश्लेषकों का मानना है कि, पाकिस्तान निश्चित तौर पर भागीदारी करना चाहेगा, लेकिन उसकी भूमिका क्या होगी, इसपर शक है।

क्योंकि, पाकिस्तान के पास निवेशक बनने के लिए पैसे नहीं है और प्रोजेक्ट में पाकिस्तानी मजदूरों को शामिल नहीं किया जाएगा, लिहाजा पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में बतौर व्यापारी एंट्री करना काफी मुश्किल होगा।

बेहद दुर्लभ धातु है लिथियम

इन सब खनिजों में से लिथियम की मांग के कारण अफगानिस्तान को 'सऊदी अरब' भी कहा जाता है। दरअसल, कार से लेकर लैपटॉप और मोबाइल की बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल होता है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने ही कहा था कि अफगानिस्तान का लिथियम सऊदी अरब बन जाएगा। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए यह तय है कि आने वाले वक्त में जीवाश्म ईंधन की जगह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में लिथियम जैसे खनिजों की भारी मौजूदगी अफगानिस्तान की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है, बशर्ते उसका सही तरीके से इस्तेमाल है और वो इस्तेमाल अफगानिस्तान के अंदर बनने वाली सरकार करे। उसपर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण ना हो।

जीभ लपलपा रहा है ड्रैगन

अफगानिस्तान में नरम धातु नाइओबियम भी पाया जाता है, जिसका उपयोग सुपरकंडक्टर स्टील बनाने के लिए किया जाता है। और आपको बता दें कि सुपरकंडक्टर कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस साल नामी कार कंपनियों को सुपरकंडक्टर के अभाव की वजह से अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा है। वहीं, अभी भी वैश्विक कार बाजार में प्रोडक्शन काफी कम हो चुका है। इतने दुर्लभ खनिजों की मौजूदगी के कारण यह माना जाता है कि आने वाले समय में दुनिया तेजी से खनन के लिए अफगानिस्तान की तरफ रुख करेगी। अब तक अमेरिका यहीं बना हुआ था और उसने एक तरह से अफगानिस्तान की खनिज संपदा की रक्षा ही की है, लेकिन अब चीन अफगानिस्तान तक पहुंच गया है।

अफगानिस्तान का दोहन करेगा चीन?

चीन ने अफगानिस्तान में मौजूद उस दुर्लभ खजाने को हासिल करने के लिए करीब 62 अरब डॉलर की बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत अफगानिस्तान तक सीपीसी यानि चीन पाकिस्तान कॉरिडोर का विस्तार करने की कोशिश काफी तेज कर दी है। एक बार अगर बेल्ट एंड रोड परियोजना बन जाता है, तो फिर अफगानिस्तान की खनिज संपदा को चीन के हाथ में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि, सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर मची लड़ाई का फायदा उठाने में चीन कोई कमी नहीं करेगा।

अब तक गरीब क्यों है अफगानिस्तान?

एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में एक ट्रिलियन डॉलर के संसाधन हैं, लेकिन हर साल सरकार को खनन से 30 करोड़ डॉलर के राजस्व का नुकसान ही होता है। अफ़ग़ानिस्तान खराब सुरक्षा, कानूनों की कमी और भ्रष्टाचार के कारण अपने खनिज क्षेत्र को ना विकसित कर पाया है और ना ही उसकी पुरक्षा करने में समर्थ नजर आ रहा है। बिगड़ते बुनियादी ढांचे के कारण अफगानिस्तान में परिवहन व्यवस्था भी बेहद खराब है साथ ही सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो खनिजों का खनन कर सके। इन सब वजहों से खनन ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 7-10% का योगदान दिया। ऐसे में अगर चीन अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमाता है तो जाहिर तौर पर अफनागिस्तान को फायदा से ज्यादा नुकसान होगा।

सरकार इलेक्ट्रोलाइजर के अनुसंधान, विकास को बढ़ावा देने के लिये जल्द लाएगी योजना

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने बुधवार को कहा कि इलेक्ट्रोलाइजर के मामले में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिये जल्दी ही एक योजना शुरू की जाएगी। यह देश में नवकीरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में कदम है। इलेक्ट्रोलाइजर एक प्रणाली है जो रसायनिक प्रक्रिया (इलेक्ट्रोलाइसिस) के जरिये हाइड्रोजन का उत्पादन करती है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री खुबा ने यह बात सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर द्वारा यहां आयोजित हाइड्रोजन ऊर्जा - नीतियों, बुनियादी ढांचा विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। अपने संबोधन में खुबा ने सीओपी26 (जलवायु परिवर्तन सम्मेलन) में देश में कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य स्तर पर लाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को रेखांकित किया। भारत ने 2030 तक 5,00,000 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा और 2070 तक शुद्ध रूप से कार्बन उत्सर्जन शून्य स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा है। मंत्री ने आईआईटी और अन्य संगठनों के प्रौद्योगिकीविदों से हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक से अधिक शोध करने का आग्रह किया ताकि इलेट्रोलाइजर के उत्पादन की लागत को कम करने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसके लिए एक योजना ला रहा है। खुबा ने उम्मीद जतायी कि 24 नवंबर से शुरू दो दिवसीय सम्मेलन हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए भविष्य की चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने और समाधान खोजने में सक्षम होगा।सम्मेलन में देश के 60 संगठनों के करीब 200 प्रतिनिधि और जर्मनी, जापान और स्वीडन के तीन अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में हाइड्रोजन के क्षेत्र में पिछले कुछ साल में देश में हुए विकास को रेखांकित किया जाएगा।

सरकार ने पांच किलो मुफ्त खाद्यान्न योजना को अगले साल मार्च तक बढ़ाया

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राशन कार्डधारकों को राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति को मार्च, 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया। पीएमजीकेएवाई के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान दिया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन के बीच गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए यह योजना अप्रैल, 2020 में तीन महीने के लिए शुरू की गई थी। तब से इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सामान्य कोटे से अधिक पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ''पीएमजीकेएवाई को मार्च, 2022 तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।'' उन्होंने कहा कि इससे राजकोष पर अतिरिक्त 53,344 करोड़ रुपये का बोझ आयेगा। उन्होंने कहा कि पीएमजीकेएवाई की कुल लागत इस विस्तार को मिलाकर लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। पीएमजीकेएवाई को कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए संकट के दौरान तीन महीने (अप्रैल-जून 2020) के लिए शुरू किया गया था। हालांकि, संकट जारी रहने के साथ, कार्यक्रम को और पांच महीने (जुलाई-नवंबर, 2020) के लिए बढ़ा दिया गया था। महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत के बाद, पीएमजीकेएवाई को एक बार फिर दो महीने (मई-जून, 2021) के लिए शुरू किया गया था और इसे आगे पांच महीने (जुलाई-नवंबर, 2021) के लिए बढ़ा दिया गया था।

पराई होती बेटी और उसका घर-संसार

राजकुमार जैन
स्वतंत्र विचारक

आपसी बातचीत, समाचार पत्र, पत्रिका और सोशल मीडिया आदि पर पर अक्सर माता, पिता, अभिभावक और परिजन विवाह के पश्चात बिटिया के पराई हो जाने, उसके व्यवहार के बारे में अति भावुक बातें करते है, पोस्ट लिखते है और फॉरवर्ड भी करते रहते हैं, इनको पढ़कर मेरे मन में कुछ विचार आते है जो परिस्थितियों के अनुसार सही या गलत हो सकते हैं ।

बिटिया बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करनी है, शादी के बाद वो अपना घर संसार एक नई दुनिया बसायेगी, हम सभी यही सबकुछ सोचकर ही अपनी रानी बिटिया या पापा की परी का विवाह करके उसे उसके संसार में जाने के लिए नम आंखों से विदा करते हैं, शादी की चर्चा शुरू होते ही हमें मालूम होता है कि अब वो अपना नया घर संसार बसायेगी, जो उसका अपना होगा।

लेकिन शादी पश्चात विदा होते ही हम भावुक होने लगते है और जब वो उस घर को अपना घर समझकर अपना व्यवहार बदलती है, जैसे अब वो अपना पैसा खर्च करती है, हमारे लिए अपने पैसों से कुछ खरीदकर लाती है, उस घर के रीती रिवाज मानने लगती है, वहां होने वाले समारोह, कार्यक्रम उसकी प्राथमिकता में आने लगते है, नई गृहस्थी जमाने से उपजी व्यस्तता के चलते कह देती है कि बाद में फ्री होकर बात करती हूं, तो हम उसको उल्हाना देते हुए कहने लगते हैं कि अब तुम हमारे साथ परायों समान व्यवहार करने लगी हो, तुम पराई हो गई है, मत भूलो कि यह घर तुम्हारा ही है।

मेरी बहन की दो बेटियां है, बहन की शादी के बाद से ही हर वर्ष भाईदूज बड़े उत्साह से मनाई जाती है, हमारा परिवार भी बच्चों सहित उस समारोह में भाग लेता आया है, पिछले वर्ष बड़ी भानजी की शादी हो गई, इस बार भाईदूज पर उसने अपने भाईयों यानी मेरे बच्चों और उसके अन्य कजिन्स के लिए एक कार्यक्रम स्वयम के खर्च पर अपनी मां के आयोजन से इतर आयोजित किया, मुझे यह बहुत अच्छा लगा लेकिन कुछ लोग कहने लगे यह तो अभी से हमको पराया समझने लगी है और अन्य भावुकता पूर्ण बाते कहकर उस बिटिया को दुःखी करने लगे ।

हम अभिभावकों और परिजनों को यह समझना चाहिए अब उसका अपना घर है और उसे उसके अपने घर को अपना घर समझने दें और उसे अपने घर में सुख से रहने दें। विवाह के तुरंत बाद भावनात्मक रूप से सबल होने में उसकी मदद करे, उसकी भावनाओं को समझे और उसे अपना घर संसार बसाने में मदद करे, इस तरह की नकारात्मक भावनात्मक बाते कर के उसके मन को कमजोर ना करें। मेरी बात के मर्म को समझें और भावनात्मक तर्क ना करें, अब उसका अपना घर है और यह वो सच्चाई है जो उसकी मां, उसकी नानी, उसकी दादी आदि ने स्वीकारने में ना जाने कितने बरस लगा दिए थे।

वस्तुतः अपना स्वयम का घर एक ही होता है, मकान तो कई हो सकते है लेकिन घर... वो तो एक ही होता है ना ।

बिटिया को अपने घर संसार में, नए वातावरण में, नई जमीन में जड़ें जमाने दें ।

इन नासमझी से भरी और भारी मन से कही गयी भावनातमक बातों को सुनकर वो ना इधर की रह पाती है ना उधर की, उसको समझ नहीं आता कि उसका अपना घर कौनसा है ? वो उधर जमने का प्रयास करती है तो इधर वाले उसे खींचते है और इधर आती है तो वापस तो उधर जाना ही होता है ।

तो उसके लिए, हम लोगों के लिए और सबके हित में बेहतर यही होगा कि उसे राजी खुशी अपना निजी घर संसार बसाने दें, इस काम में उसकी मदद करें और जो मदद ना कर सकें तो कम से कम उस पर अपनी दुर्बल भावनाओं का दबाव बनाकर उसे कमजोर ना बनाएं ।

जरा सोचिए हमारे परिवार में जो बड़ी महिलाएं है उनका कहना घर कौनसा है, आपकी माँ का घर कौनसा है , आपकी दादी का घर कौनसा है, आपकी नानी का घर कौनसा है, आपकी बुआ का घर कौनसा है, क्या आप उनके मायके को उनका घर मानते हैं क्या? तो फिर अपनी बिटिया को उसका मायका क्यो बार बार याद दिलाते हैं । सोचिए, विचारिये और अपनी बिटिया को समझाइश दीजिये कि शादी के बाद वो जिस घर में गई है वो ही उसका घर है और जितनी जल्दी वो इस बदलाव (जो कि आज नहीं तो कल घटित होकर रहेगा ही) को मन से स्वीकार कर लेगी उतने ही उसके भावनात्मक दुःख कम होंगे और नये परिवार में खुशी बढ़ेगी । पक्के यकीन से नहीं कह सकता लेकिन इस तरह बिटिया को दो नावों की सवारी करवाना, समाज में बढ़ती जा रही पारिवारिक अशांति और विघटन का यह एक बड़ा कारण हो सकता है ।

स्कोडा स्लाविया: इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के तहत स्कोडा के दूसरे मॉडल का बाज़ार में आगमन

नई प्रीमियम मिड-साइज़ सेडान में का डिज़ाइन दिल को छूने वाला

वैश्विक सहयोग का प्रतीक है निर्माण पुणे,भारत में

इंदौर।आईपीटी नेटवर्क

स्लाविया के बाजार में आगमन के साथ ही इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के तहत स्कोडा ऑटो के अगले चरण की शुरुआत हो गई है। मध्यम आकार के एळ्र कुशक को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद, यह नई सेडान चेक कार निर्माता द्वारा भारत के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया दूसरा मॉडल है। स्लाविया का 95% तक निर्माण-कार्य स्थानीय स्तर पर पूरा किया गया है।

यह सेडान MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म – स्कोडा ऑटो द्वारा भारत के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया MQB वेरिएंट – पर आधारित है, जिसमें सुरक्षा के लिए बेमिसाल फीचर्स के साथ-साथ अत्याधुनिक इन्फोटेनमेंट सिस्टम मौजूद है। स्लाविया में लगाए गए TSI इंजनों का पावर आउटपुट क्रमशः 85 kW (115 PS)* और 110 kW (150 PS)* है, साथ ही स्कोडा के दूसरे मॉडल की तरह इसका डिज़ाइन भी दिल को छू लेने वाला है। इस मॉडल का नाम, कार निर्माता कंपनी की शुरुआत के प्रति सम्मान प्रकट करता है और यह भारतीय बाजार में एक नए युग का प्रतीक है।

इस मौके पर स्कोडा ऑटो के सीईओ, श्री थॉमस शेफेर ने कहा: 'नई स्लाविया के साथ, हम अपने इंडिया 2.0 प्रोडक्ट कैंपेन के अगले चरण की शुरुआत कर रहे हैं। कुशक को सफलतापूर्वक बाजार में उतारने के बाद, अब हम अपनी बिल्कुल नई प्रीमियम मिड-साइज़ सेडान के साथ एक और लोकप्रिय सेगमेंट में कदम बढ़ा रहे हैं। स्लाविया पूरी तरह से भारत में हमारे ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप है और इसका 95% तक निर्माण स्थानीय स्तर पर किया गया है। हमें यकीन है कि कुशक और स्लाविया, दोनों हमें असीम संभावनाओं वाले और निरंतर विकसित हो रहे इस बाजार का भरपूर लाभ उठाने में सक्षम बनाएंगे।'

श्री गुरप्रताप बोपाराय, मैनेजिंग डायरेक्टर, स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ने कहा: 'कुशक के साथ इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट की सफल शुरुआत हुई है, जिससे यह बात उजागर होती है कि वैश्विक सहयोग से भारत में हर लक्ष्य को हासिल करना संभव है। ग्राहकों के बीच बेहद लोकप्रिय एळ्र के अलावा, प्रीमियम सेडान सेगमेंट में भी जबरदस्त संभावनाएं हैं, और इस क्षेत्र में हमने अपनी खास पहचान बनाई है। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित स्लाविया आपकी शान और स्टाइल का प्रतीक है।

यह स्कोडा ऑटो के लिए विकास के एक नए क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। अपनी उन्नत शैली, दमदार इंजन और कई 'सिम्पली क्लैवर' फीचर्स के साथ, स्लाविया भारत में समझदार ग्राहकों को बेहद पसंद आएगी, साथ ही दुनिया भर के बाजारों में भी लोग इसे काफी पसंद करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि, ऑक्टेविया और सुपर्ब की तरह स्कोडा स्लाविया भी हर कसौटी पर खरा उतरेगा और इस सेगमेंट में हमारे वर्चस्व को और मजबूत बनाने में हमारी मदद करेगा।'

श्री ज़ैक हॉलिस, ब्रांड डायरेक्टर- स्कोडा ऑटो इंडिया, ने कहा: कुशक के लॉन्च के साथ, हमने स्कोडा ऑटो इंडिया के कारोबार में जबरदस्त वृद्धि देखी है। कुशक के जरिए हमने आधुनिक भारत की उम्मीदों का प्रतीक समझे जाने वाले मिड-साइज़ SUV के क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है, और दूसरी ओर स्लाविया हमें अपनी जड़ों की ओर वापस ले जाती है, क्योंकि हम ऑरिजिनल प्रीमियम सेडान को भारत लाने वाले ब्रांड रहे हैं। इस उद्योग जगत को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

जनधन योजना में बदलाव कर सकती है सरकार

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार एक बार फिर जनधन योजना में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसका सीधा फायदा आम लोगों को होगा। सरकार की योजना है कि लोगों के घर तक बैंक पहुंचे। इसके लिए बकायदा रोड मैप तैयार कर लिया गया है।

क्या है सरकार का प्लान

रिपोर्ट के अनुसार सरकार जनधन योजना 3.0 के तहत डोर स्टेप की सुविधा लोगों को देना चाहती है। साथ ही सरकार प्रयास कर रही है कि 5 किलोमीटर के अंदर एक बैंक हो। जिससे लोगों को बहुत भागदौड़ ना करनी हो। इसके अलावा सरकार का प्रयास है कि डिजिटल लोन के अप्रूवल में तेजी आए।

जनधन योजना के फायदे

जनधन खाता फ्री में खोला जाता है और इसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता है।

6 महीने बाद ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है।

ओवरड्राफ्ट की सीमा 10,000 रुपये ।

बिना किसी शर्त 2,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है।

जनधन खाता खोलने वाले को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे वह खाते से पैसे निकलवा सकता है या खरीददारी कर सकता है

28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रुपे कार्ड पर मुफ्त आकस्मिक बीमा कवर।

2 लाख रुपये तक एक्सिडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है।

30,000 रुपये तक का लाइफ कवर, जो लाभार्थी की मृत्यु पर योगयता शर्तें पूरी होने पर मिलता है।

देश भर में पैसों के ट्रांसफर की सुविधा दी जाती है।

सरकारी योजनाओं के फायदों का सीधा पैसा खाते में आता है।

खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है।

खाते के साथ फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है।

जनधन खाते के जरिए बीमा, पेंशन प्रोडक्ट्स खरीदना आसान है।

जनधन खाता है तो पीएम किसान और श्रमयोगी मानधन जैसी योजनाओं में पेंशन के लिए खाता खुल जाएगा।

सौभाग्य सुंदरी व्रत

जानें क्या है इसका महत्व

अगहन माह में तृतीया तिथि को सौभाग्य सुंदरी व्रत किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित यह व्रत सौभाग्य और सौंदर्य प्रदान करता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान और सुखद दांपत्य जीवन का आशीष प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो भी स्त्री इस व्रत का पालन करती है उनके सुहाग की रक्षा माता पार्वती करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से दांपत्य के साथ मांगलिक दोष भी दूर हो जाते हैं। यह व्रत पति एवं पुत्र की लंबी आयु के लिए भी किया जाता है। सौभार?य सुंदरी व्रत का दिन कृष?ण पक्ष के तीसरे दिन या कृष्ण पक्ष से संबंधित है। सौभाग्य सुंदरी व्रत के दौरान, मां दुर्गा और भगवान शिव की पूजा से पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है। माता पार्वती का 16 श्रृंगार किया जाता है। नवग्रहों की पूजा के बाद भगवान शिव और मां पार्वती की एक साथ पूजा की जाती है। सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत सौभाग्य देने वाला है। संतान सुख के लिए भी महिलाएं यह व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। इस दिन सच्चे मन से व्रत रहने से दाम्पत्य जीवन का दोष दूर होता है और जिस अविवाहित कन्या का विवाह न हो रहा हो या देरी हो रही हो या वो मांगलिक है, उसके सभी कष्ट शीघ्र दूर हो जाते हैं। इसी दिन माता सती ने अपनी कठोर साधना से भगवान शिव को पाने का संकल्प किया था। सौभाग्य सुंदरी व्रत करने से स्त्रियों को अखण्ड सौभाग्य का वरदान मिलता है। शास्त्रों में सौभाग्य सुंदरी व्रत का महत्व करवाचौथ के बराबर बताया गया है। सौभाग्य सुंदरी की पूजा में सूखे मेवे, सात प्रकार के अनाज चढ़ाये जाते हैं। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है।

गुरु का राशि परिवर्तनः कुंभ राशि में बृहस्पति के आने से देश में बड़े राजनीतिक बदलाव होने के योग, 5 राशियों के लिए शुभ

21 नवंबर को बृहस्पति कुंभ राशि में आ गया है। इस राशि में तकरीबन साढ़े 4 महीने रुकने के बाद ये ग्रह अगले साल 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। बृहस्पति के राशि बदलने से शनि-गुरु की अशुभ युति खत्म हो जाएगी और बृहस्पति पर किसी पाप ग्रह की छाया भी नहीं रहेगी। जिससे इसका अशुभ असर कम हो जाएगा। बृहस्पति के राशि परिवर्तन से देश में बड़े राजनीतिक बदलाव होने के योग बनेंगे।

धर्म, शिक्षा और बैंकिंग से जुड़े बड़े फैसले

पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉ. गणेश मिश्र बताते हैं कि शनि के साथ गुरु की युति खत्म होने से अनुसंधान से जुड़े रुके काम पूरे हो सकते हैं। शिक्षा, रोजगार कला, संस्कृति, बैंकिंग और अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। शनि-गुरु की वजह से फैला बीमारियों का संक्रमण लगभग खत्म होने लगेगा। धर्म, शिक्षा और बैंकिंग से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय शुरू होगा। इन मामलों से जुड़े बड़े और अहम फैसले भी होंगे। कुल मिलाकर भगवान विष्णु के प्रभाव में वृद्धि होने से रोगों और मानसिक रूप से उपजे तनाव में कमी आनी शुरू हो जाएगी।

5 राशियों के लिए धन लाभ और तरक्की वाला समय

डॉ. मिश्र के मुताबिक 21 नवंबर से बृहस्पति सीधी चाल से चलेगा और कुंभ राशि में रहेगा। इसके प्रभाव से मेष, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि वाले लोगों को जॉब और बिजनेस में किस्मत का साथ मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन और मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है। अधिकारियों से मदद भी मिलने के योग बनेंगे। इनके अलावा बिजनेस करने वाले लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। बिजनेस में तरक्की होने की भी संभावना है। लेन-देन और निवेश समेत कई मामलों में किस्मत का साथ भी मिल सकता है।

कुंभ समेत 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

इन दिनों में वृष, कन्या और धनु राशि वाले लोगों पर बृहस्पति का मिला-जुला असर रहेगा। इन 3 राशियों के नौकरीपेशा और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा। वहीं, कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों को संभलकर रहना होगा। इन 4 राशियों के लोगों को जोखिम और जल्दबाजी से खासतौर पर बचना होगा। निवेश और लेन-देन के फैसले भी सावधानी से और किसी अनुभवी से सलाह से लेने होंगे। इन राशियों के राजनीति से जुड़े लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी।

सूर्यदेव को प्रसन्न करने से मिलेगी आर्थिक तंगी से मुक्ति

सूर्यदेव को अग्नि का स्वरूप माना गया है, अतः वास्तु शास्त्र में सूर्यदेव का विशेष महत्व माना जाता है। सूर्योदय के समय की किरणें स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम मानी जाती हैं। सूर्यदेव को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। घर में सूर्यदेव के साथ सात घोड़ों की तस्वीर पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। घर में जहां जेवरात रखे हों, वहां तांबे की सूर्य प्रतिमा लगाने से कभी आर्थिक परेशानी नहीं आती है। बच्चों के कमरे में सूर्यदेव की प्रतिमा लगाने से सकारात्मक परिणाम सामने आने लगते हैं। घर में अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है तो उस कमरे में सूर्यदेव की प्रतिमा अवश्य लगाएं। वास्तु के अनुसार रसोई घर में तांबे की सूर्य प्रतिमा लगाने से अन्न की कमी नहीं होती। कार्यक्षेत्र में सूर्यदेव की प्रतिमा लगाने से उन्नति के अवसर मिलने लगते हैं। घर के मंदिर में तांबे की सूर्य प्रतिमा लगाएं। सूर्योदय के समय घर के दरवाजे और खिड़कियां खुला रखें। रविवार के दिन लाल-पीले रंग के कपड़े, गुड़ और लाल चंदन का प्रयोग करें। रविवार को सूर्य अस्त से पहले नमक का उपयोग न करें। रविवार को तांबे की चीजों का क्रय-विक्रय न करें। मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव का व्रत करने से काया निरोगी होती है, साथ ही अशुभ फल भी शुभ फल में बदल जाते हैं। रसोई घर और स्नानघर में भी सूर्य का प्रकाश पहुंचे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। रविवार को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें।

घर के वास्तु से मुक्ति दिलाएंगे ये उपाय, परेशानियों से मिलेगा छुटकारा

वास्तु शास्त्र में हर दिशा और हर चीज का महत्व बताया गया है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक, हर चीज में ऊर्जा होती है, जो व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती है। वास्तु में सकारात्मक ऊर्जा के लिए हर एक चीज के रख-रखाव से लेकर उसे बनाने तक के नियम बताए गए हैं। कई बार लोग बिना वास्तु की जानकारी के अपने घर का निर्माण करा लेते हैं। वास्तु दोष के कारण घर में नेगेटिव ऊर्जा बढ़ती है। जिससे कारण गृह क्लेश, आर्थिक परेशानियां और कार्यस्थल पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी वास्तु दोष का सामना करना कर रहे हैं तो इन आसान टिप्स से घर में बिना किसी तोड़-फोड़ आप भी वास्तु दोष दूर कर सकते हैं।

बाथरूम और रसोई का दरवाजा हो आमने-सामने तो करें ये उपाय

जिस घर में रसोई और बाथरूम का दरवाजा आमने-सामने होते हैं, उसे सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। वास्तु दोष के कारण परिवार में मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। ऐसे में अगर आपके घर में भी रसोई और बाथरूम आमने-सामने बने हैं तो दोनों के बीच में एक मोटा पर्दा लगा देना चाहिए। साथ ही बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए, जरूरत पड़ने पर ही इसे खोलना चाहिए। मुख्य द्वार के वास्तु दोष को ऐसे करें उपाय- वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर वास्तु दोष होने पर व्यक्ति को कार्यस्थल पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक, मुख्य द्वार के दोष से मुक्ति पाने के लिए मेनगेट पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। इसके साथ ही द्वार पर भगवान श्रीगणेश की प्रतिमा लगानी चाहिए। मुख्य द्वार पर किसी भी तरह की गंदगी न होने दें।

नए साल में इन 8 राशियों पर रहेगी शनि की टेढ़ी नजर, देखें क्या शामिल है आपकी राशि?

नवग्रहों में शनि ग्रह की गति सबसे धीमी मानी जाती है। शनि को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में करीब ढाई साल का समय लगता है। शनि के राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। हालांकि कुछ राशियों पर शनि का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। साल 2022 में शनि कुल 8 राशियों पर प्रभाव डालेंगे। जानिए कौन-सी हैं ये राशियां-

इन राशियों पर रहेगी शनि की दृष्टिः 29 अप्रैल 2022 को शनि राशि परिवर्तन करेंगे। शनि गोचर से धनु राशि वालों को शनि की साढ़े साती से मुक्ति मिल जाएगी। शनि की साढ़े साती मीन राशि वालों पर शुरू होगी। मकर और कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़े साती चलती रहेगी। शनि गोचर से कर्क व वृश्चिक राशि वालों पर शनि ढैय्या शुरू होगी। नए साल में 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था में एक बार फिर से कुंभ से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जिसके प्रभाव से जो राशियां की दशा से मुक्त हो गई थीं, वह फिर से शनि की दशा की चपेट में आ जाएंगी। 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक धनु, मकर और कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़े साती और मिथुन व तुला राशि वालों पर शनि ढैय्या रहेगी।.

इन राशियों पर नहीं रहेगी शनि की दृष्टिः 2022 में मेष, वृषभ, सिंह और कन्या राशि वालों पर शनि की तिरछी नजर नहीं रहेगी।

घर में इन चीजों को रखने से होती है सुख-समृद्धि में वृद्धि

हर व्यक्ति जीवन में खुशहाली चाहता है। सुख-सुविधाओं भरा जीवन बिताने के लिए लोग दिन-रात मेहनत करते हैं। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी जीवन में धन-धान्य की कमी बनी रहती है। घर में धन का अभाव रहता है। वास्तु शास्त्र में धन से जुड़े कुछ उपाय बताए गए हैं। जिससे घर में सुख-समृद्धि का वास रहता है। जानिए घर में किन चीजों को रखने से सुख-समृद्धि में होती है वृद्धि-

तुलसी का पौधा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पौधे की विधि-विधान से पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।

मिट्टी का घड़ा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए घर में मिट्टी के घड़े में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पैसों की तंगी नहीं होती है।

क्रिस्टल बॉल

घर में क्रिस्टल बॉल रखना बेहद शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के दरवाजे या खिड़की के ऊपर लगाने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन का अभाव नहीं होता है।

धातु का कछुआ

घर में धातु का कछुआ उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि कछुए का मुख घर की अंदर की ओर होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।

हाथी का स्टैच्यू

हाथी का स्टैच्यू बेहद शुभ माना जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में हाथी का स्टैच्यू या हंसों के जोड़े का स्टैच्यू रखना भी शुभ माना जाता है।

श्रीलंका ने आंशिक रूप से रासायनिक उर्वरकों से प्रतिबंध हटाया

निजी क्षेत्र को आयात की अनुमति दी

कोलंबो। एजेंसी

श्रीलंका सरकार ने रासायनिक उर्वरकों पर से आंशिक रूप से प्रतिबंध हटाने और निजी क्षेत्र को इसके आयात की अनुमति देने का फैसला किया है ताकि देश के किसान खुले बाजार से इसकी खरीद कर सकें। कृषि मंत्री महिंदानंद अलुतगमागे ने बुधवार को यह जानकारी दी।

राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मई में इस द्वीपीय देश के कृषि क्षेत्र को 100 प्रतिशत जैविक बनाने के लिए रासायनिक उर्वरकों के आयात पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हालांकि, प्रतिबंध हटाने का फैसला किसानों के लगातार दबाव के कारण आया है। अलुतगमागे ने कहा, ''इस संबंध में एक गजट नोटिस जारी किया जाएगा और निजी क्षेत्र आज से रासायनिक उर्वरक, खरपतवारनाशी और कीटनाशकों का आयात कर सकेंगे।'' हालांकि, मंत्री ने जोर देकर कहा कि देश में हरित कृषि को बढ़ावा देने की नीति नहीं बदली है। पिछले हफ्ते शीर्ष कृषि अधिकारी उदित जयसिंघे ने कहा था कि रासायनिक उर्वरक आयात पर प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। उसके बाद मंत्री ने कहा था कि धान और खेती के लिए आवश्यक रासायनिक उर्वरक के आयात पर प्रतिबंध रहेगा जिसके बाद भ्रम की स्थिति थी। जयसिंघे ने संवाददाताओं से कहा था कि घरेलू स्तर पर उत्पादित जैविक खाद से उर्वरक की सभी जरूरतें पूरी करना संभव नहीं है। जयसिंघे ने कहा, ''जैविक उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 3 से 4 प्रतिशत की है।'' उन्होंने कहा, '''धान की खेती के लिए इस मौसम में 80,000 टन नाइट्रोजन की आवश्यकता है। इसे पूरी तरह से कम्पोस्ट उर्वरक से घरेलू स्तर पर पूरा नहीं किया जा सकता है।' श्रीलंका में सब्जियों की कीमतें हाल के हफ्तों में लगभग दोगुना हो गई हैं क्योंकि विरोध कर रहे किसानों ने खेती बंद कर दी है।

डी बीयर्स ने अपने नए ग्लोबल कैंपेन की घोषणा की

मुंबई ।आईपीटी नेटवर्क

डी बीयर्स ने खुद के लिए, एक-दूसरे के लिए और पूरी दुनिया के लिए प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए एक नए ग्लोबल कैंपेन की घोषणा की है। यह कैंपेन, सही मायने में कंपनी के 133 साल के लंबे इतिहास में एकदम नई और उद्देश्य पर आधारित ब्रांड रणनीति तथा नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आई डू यानी मैं वादा करता हूँ किसी व्यक्ति के इरादे को दर्शाने वाली सबसे अहम अभिव्यक्तियों में से एक है, जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरती है। दिल की भावनाओं से जुड़ा और जीवन को तुरंत एक नई दिशा देने वाला यह कथन दो व्यक्तियों के बीच साथ मिलकर अपने भविष्य को संवारने के लिए किया गया वादा है, जो हमेशा कायम रहता है। डी बीयर्स के इस नए कैंपेन में इसी तरह के प्रभावशाली वादों की अहमियत पर बल दिया गया है, और इन दो खास शब्दों को नए विचार-क्षेत्र की ओर ले जाता है, तथा इन शब्दों को व्यक्तिगत स्तर पर किए गए सभी प्रकार के वादों से जोड़कर उनके अर्थ का विस्तार करता है: जिसमें प्यार, दोस्ती, परिवार, समाज, प्रकृति और बहुत कुछ शामिल है।

डी बीयर्स ग्रुप के सीईओ, श्री ब्रूस क्लीवर, कहते हैं: एक सदी से भी अधिक समय से, डी बीयर्स ने लोगों को अपने साथी के प्रति हमेशा कायम रहने वाले अपने वादे को ज़ाहिर करने में मदद करने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। आज की नई पीढ़ी के उपभोक्ताओं के लिए इस वादे का दायरा और भी विस्तृत हो गया है: और वे व्यक्तिगत विकास के लिए खुद से किए गए वादे के साथ-साथ, अपनी दोस्ती, अपने परिवारों, समाज तथा प्रकृति एवं पूरी दुनिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता ज़ाहिर करते हैं। आज आई डू यानी मैं वादा करता हूँ का अर्थ काफी विस्तृत हो गया है और यह पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक भी है – साथ ही हीरे का प्रयोजन भी पहले से कहीं अधिक व्यापक हो गया है।

वन डी बीयर्स हमारा नया विज़न है जिसमें हमारे ब्रांड के उद्देश्य की मूल भावना समाहित है और उपभोक्ताओं को एक नए नजरिए के साथ इससे जुड़ने में सक्षम बनाता है। इस नए विज़न के साथ, हमें हीरे के भविष्य को आकार देने का एक रोमांचक अवसर दिखाई दे रहा है। अपने आईकॉनिक ब्रांड नाम के लिए मार्केटिंग में निवेश करने के साथ, हम उपभोक्ताओं के लिए डी बीयर्स के डायमंड्स की अहमियत का विस्तार करते हुए उसे दिल की भावनाओं से जोड़ेंगे, दुनिया में उनके सकारात्मक प्रभाव और हमारे ज्वैलरी हाउस के लिए चुने गए इन डायमंड्स की बेमिसाल खूबसूरती को उजागर करेंगे।

घरेलू निर्यातक जल्द कर सकेंगे अमेरिका को 'दशहरी' और 'लंगड़ा' का निर्यात

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

घरेलू निर्यातक जल्दी ही दशहरी और लंगड़ा जैसे आम का निर्यात अमेरिका को कर सकते हैं। अमेरिका ने भारत की निर्दिष्ट एजेंसियों के परीक्षण प्रमाणपत्र स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को यह कहा। भारत ने पिछले दो साल में अमेरिका को आम का निर्यात नहीं किया है। निर्धारित व्यवस्था के तहत फल और पौधों की सेहत की निगरानी से जुड़ा अमेरिकी निरीक्षक यहां आकर प्रक्रिया को देखता है। इसे निर्यात से पहले पूर्व मंजूरी प्रक्रिया कहते हैं। निरीक्षक 2020 और 2021 में नहीं आये। व्यापार नीति मंच की मंगलवार को हुई बैठक के दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने भारत से आम, अनार के निर्यात और अमेरिका से चेरी तथा पशुओं के लिये चारे में उपयोग होने वाले 'अल्फाल्फा हे' के आयात के उपायों पर काम करने पर बनी सहमति का स्वागत किया। संयुक्त बयान के अनुसार भारत से आम और अनार के निर्यात को सुगम बनाने के लिये अमेरिका दोनों फलों के लिए पूर्व मंजूरी कार्यक्रम/विकिरण के नियामकीय निरीक्षण के हस्तांतरण को अंतिम रूप देगा और भारतीय अधिकारियों को सौंपेगा। अधिकारी ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय आम फिलहाल अमेरिका को निर्यात योग्य नहीं है। लेकिन अब इसके निर्यात की संभावना बनी है क्योंकि दोनों पक्ष निर्यात को लेकर मुद्दों के समाधान पर सहमत हुए हैं। उसने कहा, ''अब हमारे निरीक्षक आम का निरीक्षण करेंगे। हमारी निगरानी व्यवस्था को अमेरिका स्वीकार करेगा। इसका मतलब है कि अब हमारे आम को उनकी प्रयोगशालाओं में परीक्षण की जरूरत नहीं है बल्कि हमारे प्रयोगशाला प्रमाणपत्र को वे स्वीकार करेंगे। इस प्रक्रिया पर सहमति बनी है। अधिकारी ने कहा, ''हम उनका प्रमाणपत्र स्वीकार करेंगे और वे (अमेरिकी निरीक्षक) प्रमाणन के लिये भारत नहीं आएंगे।'' उसने कहा, ''...इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि दशहरी और लंगड़ा जैसे आम की किस्में अब न्यूयॉर्क और दूसरे अमेरिकी शहरों में उपलब्ध होंगी। वहीं कैलीफोर्निया की चेरी दिल्ली के सुपर मार्केट में उपलब्ध होगी।'' इस बारे में भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि अमेरिका भारत के लिए एक प्रमुख बाजार है और इसकी पहुंच न केवल निर्यात को बढ़ावा देगी बल्कि आम उत्पादकों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त करने में भी मदद करेगी।

अदाणी ट्रांसमिशन ने तीन सीआईआई अवार्ड जीते

अहमदाबाद। आईपीटी नेटवर्क

भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन एवं रिटेल डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी, अदाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड (एटीएल) ने 11 नवम्बर 2021 को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के पहले ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन-सह-प्रतियोगिता में तीन पुरस्कार जीते। एटीएल के एमडी एवं सीईओ अनिल सरदाना ने बताया कि 'ल्दि;इन पुरस्कारों से परिचालन को पर्यावरण- अनुकूल करने और सस्टेनेबिलिटी पर पूरी तरह ध्यान देते हुए उत्पादकता और दक्षता बेहतर बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और हमारे बहु-आयामी दृष्टिकोण को उत्साहजनक मान्यता मिली है। सीआईआई के इन पुरस्कारों के साथ हमने जो एसएंडपी कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट (सीएसए) स्कोर में

महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, वह कॉरपोरेट जिम्मेदारियों और ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी को संयोजित करने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। कंपनी को बेस्ट-इन-क्लास प्रथाओं के साथ बेंचमार्क किया गया है और कंपनी का इरादा विश्व स्तरीय इंटीग्रेटेड यूटिलिटी बनने का है।'

सीआईआई की ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी प्रतियोगिता को चार मुख्य सस्टेबिलिटी खंडों में बांटा गया था, जिसमें मानवीय, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों को शामिल किया गया था। निर्णायक मंडल के सदस्यों के एक पैनल द्वारा उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिभागियों के विभिन्न प्रकार के केस स्टडी का मूल्यांकन किया गया। इकॉनोमिक सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में, एटीएल ने दो अवार्ड जीते: ऑक्जिलरी कंजम्पशन पर केस स्टडी हेतु ग्रीन एनर्जी एडॉप्शन के लिए प्लेटिनम अवार्ड और क्लस्टर-आधारित मेंटेनेन्स के साथ रिमोट (सेंट्रल) परिचालन पर केस स्टडी के लिए गोल्ड अवार्ड हासिल किया। एटीएल ने एन्वायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में सबस्टेशनों को हरा-भरा बनाने हेतु अपनी केस स्टडी के लिए सिल्वर अवार्ड भी जीता।

बायर ने खेती के लिए हैदराबाद में पहला ड्रोन परीक्षण किया

नयी दिल्ली। बायर क्रॉपसाइंस लिमिटेड ने हैदराबाद के पास चंदीपा में अपने बहु-फसल प्रजनन केंद्र में अपना पहला ड्रोन परीक्षण किया है। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस अवसर पर एक संदेश में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ''मुझे यह जानकर वास्तव में खुशी हो रही है कि बायर कृषि में ड्रोन के उपयोग पर एक पायलट परियोजना पर काम कर रही है।'' कंपनी ने एक बयान में मंत्री के हवाले से कहा कि भारत प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण में बड़ी प्रगति कर रहा है। कृषि उद्देश्यों के लिए इन्हें अपनाना किसानों को समृद्ध करने के सरकार के प्रयासों की दिशा में अगला कदम है।

कच्छ के मुंद्रा बंदरगाह पर एक विदेशी पोत से कई कंटेनर जब्त

कच्छ । एजेंसी

गुजरात के अडाणी पोर्ट्स ने शुक्रवार को बताया कि सीमा शुल्क और राजस्व आसूचना निदेशालय ऊ्रे की एक संयुक्त टीम ने खतरनाक माल की ढुलाई के संदेह को लेकर मुंद्रा बंदरगाह पर एक विदेशी पोत से कई कंटेनर जब्त किए है। अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एपीएसईजेड) के अनुसार जब्त किये गए कंटेनर पाकिस्तान के कराची से चीन के शंघाई रवाना किये थे और इन्हें मुद्रा बंदरगाह के लिए नहीं भेजा गया था। देश की सबसे बड़ी बंदरगाह परिचालक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि माल को गैर-खतरनाक श्रेणी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था जबकि जब्त किए गए कंटेनरों में खतरनाक श्रेणी 7 के निशान लगे हुए थे, जो रेडियोधर्मी पदार्थों की तरफ इशारा करते हैं।

एपीएसईजेड ने कहा, ''सीमा शुल्क और डीआरआई की एक संयुक्त टीम ने 18 नवंबर को मुंद्रा बंदरगाह पर एक विदेशी पोत से कई कंटेनर जब्त किये। यह कंटेनर बिना जानकारी दिए खतरनाक माल की ढुलाई के संदेह को लेकर जब्त किये गए।''

बयान में कहा गया, ''इन कंटेनरों को मुंद्रा बंदरगाह या देश के किसी अन्य बंदरगाह के लिए रवाना नहीं किया गया था। इन्हें कराची से चीन के शंघाई भेजा जा रहा था। सरकारी अधिकारियों ने जांच के लिए इन कंटेनरों को मुंद्रा बंदरगाह पर उतार दिया है।''

स्मार्टफोन के 'सार्वभौमिक प्रमाणक' के रूप में इस्तेमाल पर काम कर रहा है यूआईडीएआई : सीईओ

मुंबई। एजेंसी

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) किसी भी निवासी की पहचान के लिए स्मार्टफोन को 'सार्वभौमिक प्रमाणक' के रूप में उपयोग करने पर विचार कर रहा है। यूआईडीएआई के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। यूआईडीएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सौरभ गर्ग ने 'ईटीबीएफएसआई कन्वर्ज' शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रमाणीकरण के लिए वर्तमान में उंगलियों के निशान, आंखों (आईरिस) और वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का उपयोग किया जाता है और इसका दायरा बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। गर्ग ने कहा, ''हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन एक सार्वभौमिक सत्यापक के रूप में कैसे विकसित हो सकता है। इस दिशा में काम चल रहा है और हमें आशा है कि हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम होंगे।

नए कोच और स्लीपर प्लेटफॉर्म के साथ आयशर ने इंटर-सिटी लक्ज़री बस लांच की

बेहतर यात्रा अनुभव के लिए प्रदर्शित की इंटरसिटी कोच और स्लीपर बसें

इंदौर। संदीप सकलेचा

वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड की बिज़नेस इकाई आयशर ट्रक और बस ने इंदौर में अपनी नवीनतम कोच और स्लीपर बस श्रृंखला का प्रदर्शन किया। विशेष रूप से बनाई हुई, बस के ढाँचे की डिज़ाइन और बनावट, वॉल्वो बस इंडिया की होसकोटे, कर्नाटक स्थित कारखाने पर की गयी है, जो की आयशर के 6016 R LPO 12.4 मीटर चेसिस इंजन पर बनाई गई है, जो पीथमपुर, मध्यप्रदेश में डिज़ाइन और निर्मित की गयी है। आलिशान इंटीरियर और भविष्यात्मक डिज़ाइन के साथ ये बसें, बस यात्रा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए तैयार हैं।

इस मौके पर, आकाश पासे, प्रेजिडेंट, बस डिवीज़न, वीईसीवी ने कहा, 'मध्यप्रदेश आयशर का घर है, क्यूँकि हमारी अधिकतर निर्माण इकाइयां भोपाल, पीथमपुर, बग्गड़ और देवास में स्थित हैं। देश के बीचोबीच स्थित होने के कारण, मध्यप्रदेश इंटरसिटी बस संचालकों के लिए महत्वपूर्ण है। महामारी के बाद अब लोग वापस अपने काम पर और परिवार और दोस्तों से मिलने के लिए बस यात्रा प्रारम्भ कर रहे हैं। इन नई बसों के साथ आयशर प्रीमियम बस यात्रा करने वालो की पहली पसंद बनना चाहता है।

साथ ही साथ हम आयशर के सर्विस नेटवर्क में भी विस्तार कर रहे हैं, ताकि हम बस संचालकों की सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके और यात्रियों को सही समय पर, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान का सके। उन्होनें बताया कि आयशर और वाल्वों के ज्वाइंट वेंचर में 5 से 7 लाख से लेकर 2 करोड तक की बसें उपलब्ध है। वीई ज्वाइंट वेंचर के साथ पहली बार 60 लाख की रेंज में बाल्वों के बैंगलोर प्लांट में बनी बाडी और पीथमपुर मप्र में बनी चेचिस पर बसों का निर्माण किया जाएगा। इनकी फाइनल ऐसेंबलिंग बेंगलौर में किया जाएगा।

इनकी अनुमानित कीमत 60 लाख होगी। इन्हें खरीदार की पंसद के अनुसार कस्टमाईज करवाया जा सकेगा। आयशर बसेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बी श्रीनिवास ने बताया। 210 हार्सपावर और 1200 -1500 rpm पर 825 Nm के फ्लैट टॉर्क तक की शक्ति के साथ, ये बसें यात्रियों को उनके गंतव्य तक जल्दी पहुंचाते हुए ड्राइवरों के लिए बेजोड़ प्रदर्शन और संचालको के लिए अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ईंधन दक्षता प्रदान करती है। इन्हें पुरी सुरक्षा मानकों को पुरा करने वाले वाल्वों के कारखानें में बनाया जाएगा। उन्होनें बताया कि देश में प्रत्येक 1000 नागरिक पर 1 बस है जबकि चाईना में प्रत्येक 1000 नागरिक पर 6 बसें है।

इस कमी को पुरा करने के लिए मिड रेंज प्रीमियर केटेगरी की बसें लांच की है। इन्हें वातानुकूलित 43 सीट वाला कोच औ स्लीपर वर्शन में 30 शानदार बर्थ के साथ जारी किया गया है।

यह बसें विश्वसनीय 5.1 लीटर VEDX5 इंजन से लैस हैं, जो की वोल्वो समूह के वैश्विक BSVI प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। कोच के थिएटर जैसी सैलून की भाँती बनी बैठने की जगह, पुशबैक सीटें और एलईडी से प्रज्वलित माहौल आरामदायक लंबी यात्रा के साथ यूएसबी पोर्ट, रीडिंग लाइट, स्पीकर, एसी लाउवर और इंफोटेनमेंट सिस्टम कुछ नियमित पेशकश हैं। ड्राइवर की सहूलियत का भी इन बसों में विशेष ध्यान रखा गया है। बस का डैशबोर्ड वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है जिसमें सभी कण्ट्रोल आसान पहुँच के लिए डिज़ाइन किये गए हैं। स्टाइलिश इंजन हुड एनवीएच स्तरों को कम करने के लिए उपयुक्त रूप से बनाया गया है। बस का ढांचा मौजूदा कानून के मद्देनज़र बनाया गया है और सभी सामग्रियां अग्निरोधी होने के लिए प्रमाणित भी हैं।

आइशर पहली बार पीथमपुर में स्थित टेलीमैटिक्स आधारित रिमोट मॉनिटरिंग और अपटाइम सेंटर के माध्यम से ऑन-रोड सपोर्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह रीयल-टाइम में सहायता देने, ज्यादा अपटाइम प्रदान करने और वाहन के जीवन को बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों के लिए लाभप्रदता में वृद्धि होती है।

अदाणी सोलर ने केएसएल क्लीनटेक के साथ साझेदारी की

अहमदाबाद। आईपीटी नेटवर्क

अदाणी ग्रुप की सोलर मैन्यूफैक्चरिंग और ईपीसी शाखा, अदाणी सोलर ने भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अपने रिटेल डिस्ट्रिब्यूशन बिजनेस को शुरू करने की घोषणा की, जिसमें केएसएल क्लीनटेक लिमिटेड दोनों क्षेत्रों के लिए आधिकारिक चैनल पार्टनर है। अदाणी सोलर ने अब भारत में सोलर पैनलों के वितरण के लिए 1,000 से अधिक शहरों में अपनी पहुंच बढ़ायी है।

केएसएल क्लीनटेक के साथ इस साझेदारी के जरिये, अदाणी सोलर का लक्ष्य भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर भाग में मौजूद रिन्यूएबल एनर्जी बाजारों में तेजी से प्रवेश करना और उनका पूंजीकरण करना है। यह किफायती दर पर सस्टेनेबल सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस अपनाने की दिशा में उठा कदम होगा।

इस परिवर्तन से दोनों क्षेत्रों में आवासीय उपभोक्ताओं और कमर्शियल प्रतिष्ठानों को बहुत लाभ होने की उम्मीद है। भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की राज्य सरकारें सोलर रूफटॉप सिस्टम को प्रोत्साहन दे रही हैं। अदाणी सोलर ऑफ-ग्रिड पैनल की स्थापना से उपभोक्ताओं को बिजली कटौती के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी, जबकि अदाणी सोलर ऑन-ग्रिड पैनल बिजली की लागत को कम करने में मदद करेंगे। अदाणी सोलर ने दोनों क्षेत्रों में रूफटॉप सेगमेंट के दायरे में 130 मेगावाट के अवसर प्राप्त करने की परिकल्पना की है। इसके लक्षित ग्राहक मुख्य रूप से रूफटॉप, यूटिलिटी-स्केल, आवासीय, कमर्शियल एवं औद्योगिक (सी एंड आई), और सोलर पंप सेगमेंट में मौजूद हैं।

अदाणी सोलर के चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर, श्री रमेश नायर ने बताया कि 'रिटेल डिस्ट्रिब्यूशन क्षेत्र में केएसएल क्लीनटेक के साथ साझेदारी करके हमें खुशी मिली है। भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र ने सौर ऊर्जा की इंस्टालेशन और सप्लाई में जबरदस्त सफलता देखी है। भारत में उल्लेखनीय विकास हुआ है और वह अब एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं, जिसके कारण हम ग्राहकों को पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बाजारों में अनुप्रयोगों के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर सोलर पैनल वितरण के जरिये पावर फैसिलिटी प्रदान करने में सक्षम होंगे।

रिटेल क्षेत्र में मौजूदगी को लेकर श्री नायर ने कहा कि 'अदाणी सोलर का लक्ष्य 50ङ्ग बाजार हिस्सेदारी पर रहेगा। हमें उम्मीद है कि हम सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक रूपों के जरिये बिजली की खपत बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पाद के लिए उच्च पहुंच और विजिबिलिटी हासिल करेंगे। अदाणी सोलर ने देश भर में रिटेल क्षेत्र में अपनी मौजूदगी का तेजी से विस्तार किया है। अपने रिटेल चैनल पार्टनर्स के माध्यम से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में कंपनी की अच्छी मौजूदगी है। अदाणी सोलर इस सेगमेंट में मार्केट लीडर बना हुआ है और सभी एसकेयू में आईईसी 2016 प्रमाणन के साथ एकमात्र मैन्यूफैक्चरर्स है।

स्ट्रॉबेरी उत्पादकों के लिए वरदान बना राष्ट्रीय बागवानी मिशन

ड्रीप, प्लास्टिक मल्चींग, कैरेट व लेनी वैग लेने पर दिया जा रहा है 50 से 90 प्रतिशत तक अनुदान

औरंगबाद। एजेंसी

राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना स्ट्रॉबेरी उत्पादकों तथा अन्य किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस योजना के तहत किसानों को 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। जानकारी देते हुए जिला उद्यान पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पारंपरिक खेती के साथ-साथ किसानों बागवानी भी अपनाना होगा। समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर किसान समृद्ध होंगे तथा उनकी आमदनी दुगनी होगी। उन्होंने बताया कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों को औषधीय तथा फूलों की खेती के लिए 90 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, मशाले व सुगंधित पौधे की खेती करने पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।इसके साथ ही ग्लैडियोलस गेंदा फूल की खेती करने पर 70 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाना है।उन्होंने बताया कि पपीता की खेती करने वाले कृषकों को कुल लागत का 75 प्रतिशत अनुदान अकाउंट के तहत भुगतान किया जायेगा। डीएचओ ने बताया कि सब्जी व फल सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक करेट,लेनी वैग व मशरूम किट लेने पर लाभुकों को 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा। योजनाओं के लाभ उठाने के लिए किसानों को विभाग के बेवसाईट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।डीएचओ ने बताया कि 23नवंबर से विभाग का पोर्टल खुल गया है।इच्छुक किसान आवश्यक डाक्यूमेंट के साथ विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन कर सकते है। उन्होंने बताया कि मशुरूम की खेती व मधुमक्खी पालन करने के लिए जमीन की जरूरत नहीं है।भूमिहीन व्यक्ति भी इस तरह के महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठा सकते हैं।

एक दशक में एयर ट्रैवल सेक्टर का 'बॉस' बन सकता है भारत

कोलकाता । एजेंसी

सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि भारत में लगभग एक दशक में हवाई यात्रा में शीर्ष पर पहुंचने की क्षमता है। उन्होंने विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को हाइलाइट किया। सिंधिया ने बताया कि सरकार क्षेत्रीय और लंबी दूरी के अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर 'कनेक्टिविटी' में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

2025 तक हवाईअड्डों की संख्या मौजूदा के 136 से बढ़ाकर 220 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

सिंधिया ने कहा, '70 वर्ष में 74 हवाईअड्डे बने थे। हमने पिछले सात साल में 62 और हवाईअड्डे बनाए हैं। अब हमारे पास 136 हवाईअड्डे हैं। लेकिन यहीं पर हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा लक्ष्य 2025 तक कुल 220 हवाईअड्डों तक पहुंचने का है और इसमें हेलीपोर्ट और वॉटर पोर्ट भी शामिल हैं। हमारे सामने बहुत काम हैं, जिन्हें पूरा करना है। कल हम जेवर हवाईअड्डे (नोएडा के पास) का शुभारंभ करने जा रहे हैं।'

महानगरों को दूसरे एयरपोर्ट की जरूरत

उन्होंने कहा कि संपर्क और यात्रा के लिए एक नया बाजार खुल गया है। नागर विमानन क्षेत्र में अब विकास को दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों द्वारा संचालित किया जाएगा। पहली श्रेणी के शहर अपनी परिपक्वता तक पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ज्यादातर महानगरों को अब दूसरे हवाईअड्डे की जरूरत है और सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।